भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की नई पहल

–डॉ. योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी एवं प्रीती भारती*
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग
का. सु. साकेत पी. जी. कालेज, अयोध्या
*शोधार्थनी– समाजशास्त्र
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उ. प्र.

शोध सारांश

विश्व की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और विश्व इतिहास में ग्रामों के निर्माण की कहानी उस समय से प्रारंभ होती है, जब मानव ने घुमंतू जीवन छोड़कर एक स्थान पर रहकर कृषि कार्य प्रारंभ किया। भारत प्रारंभ से ही गांवों का देश रहा है। जिसकी आजीविका कृषि पर आधारित है किंतु वर्तमान समय में भारत के ग्रामीण क्षेत्र काफी समृद्ध हो चुके हैं। यहां बसने वाले प्रत्येक नागरिक में शिक्षा के प्रति थोड़ी बहुत जागरूकता है एवं कृषि कार्यों को उन्नत बनाने के लिए नई–नई प्रौद्योगिकियों के ज्ञान का भी पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है। मानव जीवन में नई–नई जागरूकता को लाने में प्रौद्योगिकीकरण का बड़ा योगदान रहा है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों ने समाज के सभी क्षेत्रों में नई दिशाएं प्रदान की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। भारत आज ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मजबूत केंद्र बनता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी देश के विकास की सीढ़ी है, देश को विकास की धारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम क्योंकि पलक झपकते हर पल की खबर इस माध्यम से प्राप्त हो जाती है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो इससे अछूता हो। सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक अर्थ सूचना तैयार करने, एकत्र करने, प्रोसेस करने, भंडारित करने और उसे प्रदान करने के साथ इन सब को संभव बनाने वाली प्रक्रियाओं और यंत्रों से है।

ग्रामीण जीवन की समस्याओं को हल करके एवं ग्रामीण आयोजन तथा पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान करके ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है। प्राचीन गांव आत्मनिर्भर और लघु गणतंत्र थे, उस स्थिति में ग्रामीण जीवन आनन्दमय था किंतु वर्तमान में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ग्रामों में अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्याओं ने जन्म लिया है। गरीबी, बेकारी, बीमारी ऋणग्रस्तता, कृषि एवं भूमि की समस्या, भाषा, जाति, सांप्रदायिकता एवं शिक्षा आदि की समस्याएं उत्पन्न हुई है। भारतीय ग्रामों की बिगड़ती दशा को देखकर उनके पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने समय–समय पर अनेक योजनाएं बनाई। आज भारत में पंचवर्षीय योजनाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामोद्योग के अनेक कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। अब तक भारतीय गांव जड़ता एवं स्थिरता के प्रतीक माने जाते रहे हैं किंतु अंग्रेजों के आगमन के बाद से ही यहां परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई है। ग्रामों की आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त हुई और आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सभी रूपों का परावलंबन बढ़ा है। जाति पंचायत, संयुक्त परिवार एवं ग्राम पंचायत का प्रभाव कम हुआ है। अब न्याय एक सार्वभौमिक कानूनी एवं औपचारिक विधि से होने लगा है, जिससे गांवों में अनौपचारिक नियंत्रण शिथिल हुआ है। औद्योगिकरण ने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, ग्रामीण शिल्प उद्योग छिन्न – भिन्न हो गए और अब गांव एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग बन गए हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में यातायात एवं संदेश वाहन के नवीन साधनों ने और तीव्रता ला दी है। अब ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी अंगों से परिवर्तन अनुभव किया जाने लगा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों का परंपरागत ढांचा और जीवन परिवर्तन की तीव्र प्रक्रिया से गुजर रहा है।

ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे गुजरकर राष्ट्रीय विकास भी हो सकता है और वही तकनीक के द्वारा ग्रामीण समुदाय, युवाओं, किसानों, वंचितों तथा दिव्यांगजनों को साथ लेकर ग्रामीण विकास का सपना सरोकार किया जाना संभव है। औद्योगिक क्रांतियों के शुरुआती दौर में प्रौद्योगिकी का अंतिम मकसद बड़े पैमाने पर उत्पादन था, 1990 के दशक के आरंभ में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र ऑटोमेशन के जरिए डिजिटल क्रांति का दौर देखने को मिला। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मकसद भारत को एक मजबूत डिजिटल समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था बनाना है। साथ ही इस कार्यक्रम से देश के ग्रामीण इलाकों में प्रौद्योगिकी को पहुंचाना है। प्रौद्योगिकी की मदद से आपदा प्रबंधन, बीमारी का पता लगाकर मरीजों के इलाज और कई अन्य माध्यमों से बेहतर और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। शहरों में शिक्षा और शासन प्रणाली सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित होने से प्रौद्योगिकी का सदुपयोग भली–भांति होता है, साथ ही शिक्षित नागरिक प्रौद्योगिकी का महत्व समझते हैं, वही जब ग्रामीण समाज में किसी नई प्रौद्योगिकी का समावेश करने जाते हैं तो ग्रामीण जन को उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग और फायदे के बारे में समझाना भी एक चुनौती है। ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जाती रही इस आवश्यकता की अनुभूति महात्मा गांधी को भी हुई थी। 1935 में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ के मंच से उन्होंने 'आमजन के लिए विज्ञान' नामक एक आंदोलन का आगाज किया था। इस आंदोलन के सलाहकार मंडल में जे0 सी0 बोस, पी0 सी0 रे और सी0 वी0 रमन जैसे वैश्विक शख्सियतों को रखा गया था।

सरकारी योजनाएं

डिजिटल विलेज प्रोग्राम– डिजिटल विलेज प्रोग्राम एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के गांवों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और आर्थिक रूप से जोड़ना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग इस तरह से किया जा सके कि लोगों को आजीविका अर्जित करने में मदद मिले और भविष्य में उपयोग किए जाने वाले टेक्नोलॉजी पैकजों का मानकीकरण किया जा सके। केंद्र सरकार ने 2015 में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना के दर्शन से शुरू हुआ था। सरकार ने शहर और गांव के बीच की दूरी को कम करने के लिए डिजिटलीकरण का रास्ता अपनाया। इसके तहत ग्रामीण भारत के बहुआयामी विकास को लक्षित किया गया। इस प्रकार अपनाई जा चुकी कुछ पहलों की सूची में 3G, 4 G और 5 G इंटरनेट सेवा को उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड हाईवे से जोड़ना प्रारंभ किया गया। वे नागरिक जो मोबाइल के उपयोग को लेकर बहुत सहज नहीं थे उनके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केंद्र खोलना तय हुआ ताकि उन्हें भी सरकारी सुविधाओं का लाभ सही समय पर और पूरी पारदर्शिता से मिल सके। 2003 से 2009 के बीच दक्षिण अमेरिका के 26 देशों में किए गए सर्वेक्षण से यह पता लगा कि ब्रॉडबैंड से 10 प्रतिशत की वृद्धि ने प्रति व्यक्ति जीडीपी में 3.19 प्रतिशत की वृद्धि कर दी ऐसे में भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या गांवों में रह रही है और उन्हें अब इससे जोड़ दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ना तय है।

ई–विद्या योजना– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार डिजिटल माध्यम से बजट पेश किया। महामारी के अनुभवों के साथ डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए पीएम ई–विद्या योजना की घोषणा की। महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत अन्य कमजोर वर्ग के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। पीएम मविद्या योजना के अंतर्गत 'वन क्लास वन टीवी चौनल' कार्यक्रम में 12 से बढ़कर 200 टीवी चौनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा। हर क्षेत्र में छात्रों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं

हो सकती किंतु टीवी लगभग सभी क्षेत्रों में मौजूद है ऐसे में टीवी चौनलों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022 में कुछ वोकेशनल कोर्सेज और क्रिएटिविटी कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं विज्ञान और गणित भाषा में 750 वर्चुअल लैब 75 कौशल की म प्रयोगशाला शुरू की जाएंगी। शिक्षक इसमें डिजिटल मोड से उपलब्ध होंगे और इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो के माध्यम से छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री उपलब्ध होगी।

डिजिटल यूनिवर्सिटी– डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जा रही है इसका अर्थ है कि यूनिवर्सिटी हर एक छात्र के दरवाजे पर होगी। छात्रवृत्ति गत रूप से डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से छात्र देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था में यह अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है हर विषय के लिए असीमित सीटें होने पर कोर्स उपलब्धि का सवाल खड़ा नहीं होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी लर्निंग और री लर्निंग के लिए युवाओं की तैयारी करेगी युवाओं को तैयार करेगी प्रश्न यह है कि हम वैश्विक मानकों को छू पाएंगे या नहीं। स्वयंप्रभा 32 डी.टी.एच. चौनलों का यह समूह है जिन पर विभिन्न भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले एजुकेशनल कंटेंट प्रसारित किए जाते हैं इन चौनलों को फ्री डिश या किसी भी केबल ऑपरेटर और डी.टी.एच. पर देखा जा सकता है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। पीएम विद्या पोर्टल भी लॉन्च किया गया है देश के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाएं और कोर्सेज शुरू करने की अनुमति दी गई है। 1 से 12 तक की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एक विशेष टीवी चौनल शुरू किया जाएगा इस चौनल की सहायता से उन छात्रों को टीवी के माध्यम से पढ़ने की सुविधा मिलेगी जिनकी पहुंच हाई स्पीड इंटरनेट तक नहीं है। इसके पहले स्वयं प्रभा चौनल समूह की शुरुआत की भी की जा चुकी है इसके अलावा जिन अन्य कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा सकता है उनमें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, कौशल विकास, ई–शोध सिंधु, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय और राष्ट्रीय अकादमिक डिजिटरी कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं जो की किसी भी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

डिजिटल विलेज प्रोग्राम– डिजिटल विलेज प्रोग्राम एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के गावों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और डिजिटल एवं आर्थिक रूप से जोड़ना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग इस तरह से किया जा सके जिससे लोगों को आजीविका अर्जित करने में मदद मिले और भविष्य में उपयोग किए जाने वाले टेक्नोलॉजी पैकेज ओ का मानकीकरण किया जा सके।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)– सीएससी डिजिटल सेवा प्रदाताओं के दुनिया के सबसे विस्तृत नेटवर्क में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर तक लोगों की मदद करने वाले इन केंद्रों की पहुंच व्यापक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ यह आईसीटी सक्षम की ओर कई सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

भारत नेट योजना– भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती कीमत पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के लिए अपनी डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में इस योजना की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और अलग–अलग स्थानों में बसे नागरिकों को सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुलभ होंगे।

डिजिटलीकरण का फोकस– डिजिटलीकरण का प्राथमिक लक्ष्य हर ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों की पहुंच प्रदान करना है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट के उन्नत बुनियादी ढांचे से बेहतर कृषि शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं।

कृषि– कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार मदंउ मंडियों को जोड़ा है

ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति का सहारा 'तारा' योजना– विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार के सीड अनुभाग के अंतर्गत एक योजना तारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर रूरल एरियाज को संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीविकोपार्जन में सहायता और सामाजिक लाभ के ऐसे गैर सरकारी संगठनों को सहायता पहुंचाना है जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस योजना में नवाचार इनोवेशन और प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुकूलन पर बल दिया जाता है इसमें स्थान विशेष की आवश्यकता हो या समस्याओं के निरूपण हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को आजमाने से पूर्व इसको क्षेत्र परीक्षण किया जाता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दूर करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कौशलों का विकास करने करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है इस योजना का लाभ 5.5 करोड़ ऐसे युवाओं को मिलने की उम्मीद है जो कुशल हैं। यह योजना 'मेक इन इंडिया' के मुख्य भागीदार है। इसका लाभ हाशिए पर खड़े ग्रामीण युवाओं को मिलेगा। समाज के वंचित समुदायों के साथ–साथ दिव्यांगजन और महिलाओं को भी कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। इस योजना को तीन स्तरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है– नीति निर्माण, तकनीकी सहायता और सरलीकरण। योजना की क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा युवाओं में कौशल विकास और प्लेसमेंट के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत युवाओं को स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, चमड़ा, विद्युत आदि अनेक उद्यमों में प्रशिक्षण तथा अनुदान प्रदान किया जाता है।

सीड योजना– डीएसटी की सीड (साइंस फॉर इक्विटी एंपावरमेंट एंड डेवलपमेंट) योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर तकनीकी सशक्तिकरण तथा सतत जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत अभिप्रेरित वैज्ञानिक और शोधार्थियों की समाज से वंचित वह गरीब समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त विज्ञान व तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाता है। पिछले 200 वर्षों में मानव समाज ने तकनीक के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति की है इसमें रेलवे, हवाई जहाज, तार व टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा तथा अन्य चमत्कार पूर्व साधनों का आविष्कार कर डाला है। ये साधन मानव समाज को एक इकाई के रूप में जोड़ने तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध एवं संगठित आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन का निर्माण करने में बहुमूल्य भौतिक सामग्री सिद्ध होते हैं।

ग्रामीण युवाओं के जीवन में शिक्षा के परिवर्तित आयामों में प्रयोग प्रमुख स्टार्टअप्स–

डिजिटल लाइब्रेरी– यह शिक्षण स्टार्टअप है, जो सभी विधाओं में पुस्तकों का एक डिजिटल स्रोत प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एप्स को डाउनलोड करने और पढ़ने के लिए रियल टाइम उच्च गुणवत्ता पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है।

दीक्षा– यह शिक्षण की सभी विधाओं में पुस्तकों का एक डिजिटल स्रोत प्रदान करता है इसका उद्देश्य ई–बुक्स को डाउनलोड करने और पढ़ने के लिए रीयलटाइम उच्च गुणवत्ता पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है।

इजी नौकरी– यह स्टार्टअप नौकरी चाहने वाले ग्रामीणों को देशभर के शहरों में अवसरों से जोड़ता है इस तकनीक समर्थित मंच का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र की नौकरियों के लिए देश की भर्ती प्रक्रिया को बदलना है। यह नौकरी चाहने वालों के व्यक्तिगत विवरण अनुभव और प्रतिभा पुष्टि के बाद संभावित नियोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है।

नीवी– यह वंचितों के लिए एक शिक्षण स्टार्टअप है ताकि शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण की कमी व अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में किसी व्यक्ति का विकास बाधित ना हो यह बेघरों को आश्चर्य समर्थन के साथ युवा उद्यमियों के लिए चिकित्सा शिविर, सूक्ष्म ऋण, सीड फंडिंग भी आयोजित करता है।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के सफल उदाहरण

ग्राम ज्ञान केंद्र (बीकेसी)– एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन (एम.एस.एस.आर.एफ.) द्वारा 1998 में शुरू किया गया यह भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसमें सूचना संचार तकनीकीयों (आई. सी. टी. एस.)का कृषि हेतु विकास हेतु प्रयोग हुआ।

भूमि परियोजना– वर्ष 1998 में कर्नाटक सरकार ने भूमि परियोजना के अंतर्गत पूरे राज्य के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया।

ई–चौपाल– आईटीसी द्वारा जून 2020 में शुरू किया गया। किसानों द्वारा प्रबंधित ग्रामीण इंटरनेट किऑस्क जिन्हें संचालक कहा जाता है। किसानों को मौसम और बाजार की कीमतों पर अपनी स्थानीय भाषा में तैयार जानकारी पहुंचाते हैं जिससे किसानों को कृषि से संबंधित सभी इनपुट एवं बाजार की सही जानकारी समय पर मिलती है।

किसान कॉल सेंटर– किसान कॉल सेंटर 2004 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के प्रश्नों के उत्तर उनकी मूल भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे किसान एक टोल फ्री नंबर 18001801551 डायल कर अपनी समस्या तकनीकी कार्यकारी या वैज्ञानिक को प्रातः 6:00 से रात 10:00 बजे के बीच कभी भी दर्ज करा सकता है जिसका समाधान तुरंत या अधिकतम 72 घंटे में दे दिया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार– बाजार में खरीदार या व्यापारी की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना ही एपीएमसी मंडी में कृषि विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार का गठन किया गया ई राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य एपीएमसी में भौतिक उपस्थिति तथा बिना किसी पूर्व शर्त के खरीददारों तथा किसानों के मध्य खरीदारी करवाना है साथ ही राष्ट्रीय कृषि बाजार पूरे राज्य में व्यापार के लिए वैध एक लाइसेंस और एकल कर की स्थापना भी करता है।

कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना(एन. ई. जी. पी. ए.)–कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना एन. जी.पी. नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरु में 2010–11 में 7 पायलट राज्यों में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कृषि तक समय पर पहुंच के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपयोग के माध्यम से भारत में तेजी से विकास हासिल करना है। म गवर्नेंस योजना में स्मार्ट कृषि के नवीन प्रबंधन प्रारूप जैसे रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली जी आई एस0, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेंसर, ब्लॉकचेन शामिल किए गए हैं।

निष्कर्ष–

सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास ने ग्रामीण जीवन की काया ही पलट दी है। प्रौद्योगिकी की नवीन पद्धतियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को काफी आसान और बेहतर बना दिया है ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भौतिक वित्तीय अवसंरचना अच्छी नहीं थी वहां डिजिटल सुविधा के माध्यम से लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा गया है इससे न केवल नए उद्यमों के लिए ऋण लेना आसान आसान व सस्ता हुआ है बल्कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को भी लाभार्थी तक पहुंचाया जा सका। गैस सिलेंडर सब्सिडी किसान सहायता आदि में यह प्रयोग काफी सफल रहा वित्तीय क्षेत्र में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि इसके तहत ग्रामीण घरों तक

बैंकों की सुविधाएं पहुंचाई गई तथा लोग घर बैठे जमा व निकासी जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने लगे इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के आगमन से ग्रामीण क्षेत्रों में और भी बदलाव आए जिससे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल चुकी है। अटल इन्नोवेशन मिशन का नाम भी अहम है। इसका उद्देश्य एक मिलियन बच्चों को नवोन्मेषी बनाना है। इसी मिशन के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग मैप स्थापित किए जा रहे हैं ताकि युवा मन को जिज्ञासु रचनात्मक और कल्पनाशील बनाया जा सके। निश्चित ही यह प्रयास भविष्य के भारत को अधिक ऊर्जावान और रचनात्मक बनाएंगे। जिससे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह कटार ,2017, ग्रामीण विकास सिद्धांत की नीतियां एवं प्रबंध, सिंह पब्लिकेशन, सिंधु।
2. कुरुक्षेत्र, मई 2022, ग्रामीण विकास को समर्पित कौशल विकास।
3. कुरुक्षेत्र, नवंबर 2020, ग्रामीण विकास को समर्पित स्टार्टअप्स।
4. चक्रवर्ती दीपक, 2012, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, आर्य पब्लिकेशन।
5. कुरुक्षेत्र, नवंबर 2022, विज्ञान और तकनीक।

❑